भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2650

उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

सोमवार, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

आईटीआई में कम नामांकन

2650. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सरकारी और निजी आईटीआई में कम नामांकन दरों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी और निजी आईटीआई दोनों में कम नामांकन प्रतिशत के प्रमुख कारकों का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी आईटीआई में किफायती शुल्क संरचना सुनिश्चित करने और इनमें प्रवेश सुलभ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीआई को बढ़ावा देने के लिए उपाय लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) खराब प्रदर्शन करने वाले आईटीआई की निगरानी कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) देश में कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईटीआई स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट पहल की जा रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) महोदय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन करता है।

आईटीआई लंबे समय से, घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न ट्रेडों में लगातार कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराते रहे हैं। आईटीआई में, 168 राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुकूल ट्रेडों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक ट्रेड का एक विशिष्ट पाठ्यक्रम है। प्रशिक्षण की अवधि छह महीने से दो साल तक होती है। पाठ्यक्रमों को ट्रेडों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि प्रशिक्षु को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

वर्तमान में देश में 14,612 आईटीआई मौजूद हैं, जिनमें से 3,316 राजकीय आईटीआई और 11,296 निजी आईटीआई हैं।

आईटीआई की स्थापना और दैनन्दिन का अभिशासन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि संबद्धता के लिए मानदंड निर्धारित करने, प्रमाणन सहित परीक्षा आयोजित करने और पाठ्यक्रम तैयार करने जैसी नीतियां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हैं। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन डीजीटी द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आईटीआई में प्रशिक्षुओं को प्रवेश देते हैं। तथापि, आईटीआई में कम नामांकन के मुद्दे पर डीजीटी द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है और आईटीआई में छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समितियां (एसएसडीईसी) गठित की गई हैं, ताकि स्थानीय विद्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके, जिसका उद्देश्य दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को आईटीआई में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।

ii. एसएसडीईसी को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह पात्र अभ्यर्थियों को वॉक-इन प्रवेश देकर रिक्त सीटों को भरने का प्रयास करें।

iii. सीटीएस के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को उद्योगों के परामर्श से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, ताकि नवीन प्रौद्योगिकीय प्रगति और उद्योग की आवश्यकताओं को इनमें

समाविष्ट किया जा सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रासंगिक बने रहें और आईटीआई में इसकी मांग भी बनी रहे।

iv. डीजीटी ने आईटीआई के लिए आंकड़ा आधारित ग्रेडिंग तंत्र (डीडीजीएम) नामक एक ग्रेडिंग पद्धति शुरू की है जो पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर सभी आईटीआई का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करती है। प्रशिक्षु नामांकन और भागीदारी में सुधार करने के प्रयोजनार्थ आईटीआई को प्रोत्साहित करने के लिए नामांकन प्रतिशत को मापदंडों में से एक बनाया गया है।

v. प्रत्येक वर्ष, सीटीएस का प्रवेश कैलेंडर प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के शुरू होने से काफी पहले उपलब्ध करा दिया जाता है, ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीटों का अधिकतम उपयोग कर सकें।

vi. इनके अलावा, आईटीआई में प्रशिक्षुओं के नामांकन में सुधार करने के लिए नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श भी किया जाता है।

महोदय, डीजीटी ने निजी आईटीआई द्वारा ली जाने वाली प्रमाणिक शुल्क के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश प्रशिक्षुओं के लिए उचित और किफायती शुल्क संरचना सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे देश भर में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुलभता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीआई की स्थापना को प्रोत्साहित करने और सुलभता में सुधार करने के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित आईटीआई के लिए प्रमाणिक शुल्क संरचना को एक समान रखा गया है।

वर्तमान में, देश भर में 14,612 आईटीआई मौजूद हैं, जिनमें से 10,952 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

(घ) महोदय, डीजीटी ने आंकड़ा आधारित ग्रेडिंग तंत्र (डीडीजीएम) लागू किया है, जो पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर सभी आईटीआई का स्वतः मूल्यांकन और ग्रेडिंग करता है। यह तंत्र खराब प्रदर्शन करने वाले आईटीआई की पहचान करने में मदद करता है और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लक्षित सुधारात्मक उपायों को सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, डीजीटी ने हाल ही में 21,069 इकाइयों की संबद्धता समाप्त कर दी है, जिसमें आईटीआई की 4.49 लाख सीटें शामिल हैं, जो पिछले 6 शैक्षणिक सत्रों (2018-19 से

2023-24) से खाली पड़ी थीं। इस उपाय से सरकारी और निजी दोनों प्रकार के आईटीआई में नामांकन प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार होगा।

(ड.) सीटीएस के तहत पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रमों को उद्योगों के परामर्श से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति और उद्योग की आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रासंगिक बने रहें और आईटीआई में इनकी मांग भी बने रहें। इसके अलावा, डीजीटी ने आईटीआई प्रशिक्षुओं की नियोज्यता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की हैः

i. सीटीएस के तहत प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियोज्यता कौशल पर एक अनिवार्य विषय शामिल है। यह मॉड्यूल व्यवहार, संप्रेषण, आईटी प्रवीणता, कार्य नैतिकता, और अन्य

विशेषताओं जैसे आवश्यक कौशलों पर केंद्रित है जो एक प्रशिक्षु की दलगत भावना से काम करने और पेशेवर माहौल में टिकने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

ii. डीजीटी ने दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली योजना शुरू की है जिसमें प्रशिक्षण का (डीएसटी) एक बड़ा हिस्साहैंड्स ऑन है और उद्योग में ही प्रदान किया जाता है।

डीएसटी कार्य ढांचे में, 1 या 2 वर्ष की कुल अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए उद्योगों के भीतर 6-12 महीने तक की अवधि के लिए ऑनआयोजित किया (ओजेटी) जॉब प्रशिक्षण-द- जाता है। यहगहन दृष्टिकोण उद्योग में हासिल किए गए हैंड्स ऑन व्यावहारिक अनुभव के साथ आईटीआई में सैद्धांतिक शिक्षा को एकीकृत करता है।

*****